रोष भी व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ती जा रही है।

पहले तो उपभोक्ता टेलीफोन की लाइन की गड़बड़ी, टेलीफोन का काम नहीं करने की वजह से परेशान थे और अब एक मुसीबत आ गई है, और वह है गलत ढंग से हजारों रुपये के टेलीफोन बिल भेजने की। मेरा टेलीफोन नं० 387182 है. उसका एस टी डी भी कटा हुआ है लेकिन उसके बाद भी करीब चार हजार कालज की अतिरिक्त रकम बेतन से काट ली गई है और पता नहीं कब तक कटती रहेगी। बेतन के नाम पर "निल" मिल रहा है।

आश्चर्य तो तब होता है कि जिस समय मैं दिल्ली से महीनों बाहर था और टेलीफोन में ताला लगा था, उस समय भी पांच हजार से अधिक लोकल कालज का उपयोग मेरे द्वारा दिखलाया गया है। इस तरह की शिकायतें काफी संसद-सदस्यों ने की हैं। जब संसद-सदस्यों के साथ यह धांधली हो रही है, तो आम उपभोक्ताओं के साथ क्या होता होगा ? बिहार में टेलीफोन में व्याप्त धांधली, टेलीफोन के काम नहीं करने, गलत बिल भेजने आदि समस्याओं के विरोध में हजारों उपभोक्ताओं ने पिछले दिनों प्रदर्शन किए और करीब पाँच सौ टेलीफोन सरकार को वापस कर दिए। आम उपभोक्ताओं में काफी रोष है।

मैंने टेलीफोन में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में कई बार संचार मंत्री को पत्र लिखा और मंत्री महोदय की तरफ से एक ही घिसा-पिटा जवाब भी आ गया। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व भी संचार मंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन क्या जवाब आयेगा, वह मुझे मालूम है।

अत : आप स्वयं आम उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करें और सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश दें, जिससे देश के लाखों टेलीफोन उपभोक्तों को राहत मिल सके।

(vii) SUPPLY OF WHEAT TO BIHAR IN VIEW OF DROUGHT AS WELL AS FLOODS IN THE STATE.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ और दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में व्याप्त सूखे की स्थिति ने बिहार निवासियों को भारी संकट में डाल दिया है। इस पर तुर्रा यह कि बिहार की गरीब और पिछड़ी जनता भारत सरकार का कोप भाजन बन गई है। ऐसे सरकार कहने को तो कुछ भी कह ले, पर वास्तविकता यही है कि वह बिहार-वासियों को बड़ी ही उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। उदाहरण के लिए बिहार को दिए जाने वाले गेहूं के माहवारी कोटे को हम ले सकते हैं।

अप्रैल, 1978 से ले कर अगस्त, 1979 तक बिहार सरकार को प्रति-माह एक लाख टन गेहूं मिलता रहा। परन्तु दुख है कि भारत सरकार बिहार को मिलने वाले गेहूं के कोटे को धीरे धीरे काटती गई। इस प्रकार एक लाख टन गेहूं के कोटे को घटा कर 75 हजार टन कर दिया गया। 1980 में उसमें भी कमी कर के 60 हजार टन कर दिया गया। अगस्त, 1980 में कोटे को 30 हजार टन किया गया और बाद में तो उसे 20 हजार टन माहवारी कर दिया गया। परन्तु क्षोभ की बात तो यह है कि इस साल जुलाई से बिहार की आठ करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए केवल 12 हजार टन गेहूं दिया जा रहा है।

गेहूं में इस भारी कटौती के कारण बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा रही है। राशन की दुकानों में गेहूं के अभाव में खुले बाजारों में उसका मूल्य बहुत बढ़ गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में तो गेहूं मिलना भी मुश्किल हो गया है। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संकटकालीन पत्र (एस ओ एस)

[श्री रामावतार शास्त्री]

भेज कर भारत सरकार से गेहूं के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है।

बिहार को प्रत्येक माह में 40 हजार टन चीनी की आवश्यकता है, पर मिलती है केवल 27 हजार मैट्रिक टन। ऐसा खाद्य निगम की ढिलाई के कारण होता है। इतना ही नहीं; खाद्य निगम द्वारा बिहार के लिए समय पर चीनी नहीं उठाने के कारण बिहार के कोटे की तमादी हो जाती है।

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता की खूब ढोल पीटती है। पर बिहार की स्थिति ने यह दिखला दिया है कि सरकारी ढोल में पोल ही पोल है। अतः कृषि मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि वह पहले की तरह बिहार को मिलने वाले गेहूं की मिकदार को माहवारी एक लाख टन तो अवश्य ही कर दें। ऐसा कर के ही वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संकट को कुछ हद तक दूर कर सकते है, अन्यथा बिहार की जनता को भुखमरी से कोई नहीं बचा सकेगा। आशा है कि सरकार का ध्यान इस ओर फौरन आकृष्ट होगा।

(vii) NEED TO REDUCE AIR FARE BETWEEN AGARTALA AND CALCUTTA.

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West) : Mr. Deputy-Speaker Sir, I am drawing the attention of the House to the probelm of air link between Tripura and the rest of the country. Recently, the Central Government has enhanced the air fare from Agartala to Calcutta along with other parts of the country. Now the air fare between Agartala and Calcutta is Rs. 228/-

A few years back, the rate was only Rs. 84/- and, within a short time, the rate is increased so rapidly that it has become unbearable for the people of Tripura where 83 per cent of the population are living below the poverty line. Sir, you know that Tripura is situated in the remotest corner of the country and air link is the main means of transport with the rest of India. The people have to depend upon the air link to go outside of the State for medical treatment and other purposes and air travel is essential and not a luxury to the people of Tripura. The people of other parts of the country can avail of the railway and other modes of transport. But in the case of Tripura, these facilities are almost absent.

In veiw of the above, I urge the Government to reconsider the decision and exempt the recent increase in air fare for Tripura and North Eastern Region and introduce a cheaper service between Agartala and Calcutta as it existed previously.

I demand that the Minister concerned may make a statement in the House about the decision of the Government as early as possible.

(ix) STARTING OF MURADABAD, DELHI EXPRESS TRAIN FROM BAREILLY AT 6.00 A.M.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

मुरादाबाद से प्रातः लगभग 6 बजे दिल्ली को चलने वाली मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली में चलाये जाने की मांग बहुत समय से की जाती रही है। रात्रि के 1-40 बजे के पश्चात् बरेली से मुरादाबाद हो कर दिल्ली आने के लिए अगले दिन सायंकाल साढ़े सात बजे से पूर्व कोई ट्रेन नहीं है। अतः बरेली, बदायूं पीलीभीत,